

SHRI OM MEHTA: These night shelters are run on a voluntary basis. Those who want can go and stay there. We cannot forcefully remove people to the night shelters.

SHRIMATI M. GODFREY: The police should round up these people and keep them in the night shelters. Then they would be doing a service to the pavement dwellers.

Massive Dairy Development Programme in Rural Areas

*163. **SHRI R. N. BARMAN:** Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are considering a scheme of "Massive Dairy Development Programme" in rural areas; and

(b) if so, the places of rural areas in West Bengal likely to be considered under this scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI B. P. MAURYA): (a) Government has taken concrete steps towards a large dairy and cattle development programme in rural areas during the 4th five-year plan and these are proposed to be continued in the 5th five-year plan. Besides providing essential inputs for cattle development, cross breeding of cattle with exotic inheritance, establishment of semen banks and artificial insemination facilities are provided through these projects. 62 such projects have been established so far in various States. A target for 51 additional I.C.D.Ps is envisaged during the 5th five-year plan.

Besides, ICDPs, cattle and dairy development is also assisted through key village scheme. 622 key village blocks are functioning at present and it is proposed to increase the number of 713 shortly.

Development of dairy farming on modern scientific lines has also been

undertaken in collaboration with foreign countries. Indo-Swiss Project, Muzer (Kerala State), Nabha (Punjab), Indo-Danish Project Hesarghatta (Karnataka) Indo-German Project, Mandi (Himachal Pradesh), Indo-Austrian Project, Hissar (Haryana State), Barpetta (Assam) have great potentials in this field.

(b) Two I.C.D.Ps., are in progress at Barasat and Krishnanagar in West Bengal. Two additional I.C.D.Ps., one at Malda and the other at West Dinajpur are to be set up shortly. It is proposed to set up three more I.C.D.Ps., during the 5th plan period. In addition, 62 key village blocks are functioning at present in various parts of the State

SHRI R. N. BARMAN: May I know from the hon. Minister by what time these dairies will start functioning?

SHRI B. P. MAURYA: Very soon they will start functioning. I do not know whether the hon. Member is keen to know about his constituency, West Dinajpur or about others also. About West Dinajpur, it will be commissioned quite soon.

SHRI R. N. BARMAN: What is the total amount the Government propose to spend for these dairies in West Bengal and what is their exact location?

SHRI B. P. MAURYA: It is given in my reply and specially I will mention that in the Fifth Five Year Plan it is proposed to set up seven dairy plants and of which we will cover five in the first year of the Fifth Plan.

श्री कमल निथ मधुकर : मैं यह जानना चाहता हूँ कि बिहार में ऐसे डेयरी फार्मों की कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं, उनको किन-किन स्थानों में लागू किया जायेगा और उनका काम कब तक शुरू हो जायेगा ।

श्री. श्री० पी० मोर्य : बिहार प्रदेश के आंकड़े तो मेरे पास हैं और अगर माननीय सदस्य चाहें, तो मैं दे सकता हूँ। लेकिन स्थानों के बारे में जानकारी के लिए नोटिस की आवश्यकता होगी। बिहार में डेयरी फार्म की तीन योजनाएँ हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में आठ योजनाएँ चलाने का निश्चय किया गया है और उनमें से चार पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में ही ले ली जायेगी।

SHRI K. MALLANNA: May I know from the hon Minister as to what is the total installed capacity of the dairy plants and are they working to the full capacity and if not, what are the reasons?

श्री श्री० पी० मोर्य : सब डेयरी फार्मों की इनस्टाल्ड कैपेसिटी आदि बताने के लिए नोटिस की आवश्यकता होगी। जहाँ तक दिल्ली की डेयरी का प्रश्न है, उस में दूध का उत्पादन आस-प्रतिशत हो रहा है। उसमें दूध का उत्पादन 2.86 लाख लिटर रोजाना होता है और उसकी इनस्टाल्ड कैपेसिटी भी लगभग उसी ही है। बम्बई की डेयरी की इनस्टाल्ड कैपेसिटी करीब 6 लाख लिटर प्रतिदिन है और वहाँ 5.37 लाख लिटर प्रतिदिन दूध का उत्पादन हो रहा है—वह अपनी कैपेसिटी से कुछ कम उत्पादन कर रही है, उस का उत्पादन कैपेसिटी के लगभग ही है।

श्री. श्री० पी० मोर्य : मंत्री महोदय ने बताया है कि हम विदेशों की सहायता से डेयरियों का विकास करना चाहते हैं। गर्मी के दिनों में देश में दूध की बहुत कमी हो जाती है। क्या उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार विदेशों से मिल्क-पाउडर भी लाना चाहती है; यदि हाँ, तो कितना और वह किस हिसाब से बाँटा जायेगा? दूध देने वाले पशुओं को आज भी बड़ी संख्या में काटा जाता है। क्या इसको बन्द करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई योजना

है? पशुओं को ठीक खुराक न मिलने की वजह से उनका दूध सूख जाता है। क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि उनको ठीक खुराक मिले, ताकि वे अच्छा दूध दें?

श्री श्री० पी० मोर्य : जहाँ तक विदेशी सहायता का प्रश्न है, हमको बहुत से विदेशों का सहयोग चाहिए और बहुत से विदेशों को हमारा सहयोग चाहिए। हमको कोई बुरी भावना में नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक पाउडर का प्रश्न है—618 डब (गैल० पी० (मै। गन फलड) में कुछ पाउडर आगन के लिये निश्चिन किया जाता है, उम्मी के अन्नगन जितना कर सकते हैं, करत है, लेकिन विदेशों से ज्यादा मगाने के लिये विदेशी मद्रा की आवश्यकता होगी—जिसकी पहले ही दिक्कत है।

श्री. श्री० पी० मोर्य : दूध देने वाले पशुओं को बड़ी मात्रा में काटा जाता है, उसके बारे में आपने नहीं बतलाया?

श्री श्री० पी० मोर्य : जहाँ तक दूध देने वाले पशुओं के काटने का प्रश्न है, बहुत से प्रदेशों ने ऐसा कानून बना दिया है कि उनको न काटा जाय, लेकिन जिन प्रदेशों में नहीं बने—वह बात उन प्रदेशों से ही सम्बन्ध रखती है।

SHRIMATI ROZA DESHPANDE: Will the hon. Minister please tell me whether the supply of milk in Bombay City is sufficient and if not, may I know whether the hon. Minister knows that there have been several agitations over it and the price-rise in milk and what Government thinks about it?

SHRI B. P. MAURYA: So far as the necessity of Bombay town is concerned, that is roughly 13 lakh litres a day. As I have already submitted, the total supply at present from our dairies is about six lakh litres a day. Almost fifty per cent shortage is there. At present the standard milk which is being supplied in Bombay by our dairies is having 5.5 per cent

fat and 9 per cent SNF, while the toned milk that is being supplied is having 3.5 per cent fat and 8.5 per cent SNF. For that they will need extra powder. We can increase their capacity upto seven lakh litres a day. That is under the consideration of the Ministry.

डा० कंसलत : माननीय मंत्र जी से अपने उत्तर में—महाराष्ट्र के सम्बन्ध में पांचवीं पंचवर्षीय योजना में क्या करने जा रहे हैं—इस बात का उत्तर नहीं दिया है। इसका अर्थ यह हो जाता है कि महाराष्ट्र के प्रति इन्होंने विश्वास प्रकट नहीं किया है। महाराष्ट्र के मायने बम्बई से ही नहीं हैं, इसमें पूना, शोलापुर, नागपुर, नासिक भी शामिल हैं जहां दूध की बहुत कमी है—इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि मंत्रालय इन क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्या कदम उठाने जा रहा है ?

श्री बी० पी० मोर्य : इन्टेसिव कैटिल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1973-74 महाराष्ट्र में 6 थे और हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश में 6 से ज्यादा नहीं हैं, चाहे उनकी पापुलेशन महाराष्ट्र से ज्यादा हो। ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं, जिनमें एक प्रोजेक्ट पर 1 करोड़ रुपया खर्च आता है। पांचवीं योजना में वहां 10 प्रोजेक्ट रखे गये हैं, जबकि 10 से ज्यादा किसी भी प्रदेश में नहीं हैं—इसलिये महाराष्ट्र के साथ किसी दूसरी भावना का उपयोग नहीं किया गया है, महाराष्ट्र के साथ तो ज्यादा अच्छा व्यवहार किया गया है, उदाहरण के लिये अनुपात बनता है थोड़ा-बहुत उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है।

श्री मधु लिमये : क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है—कि बम्बई की आरे-कालोनी एक सफेद हाथी है, जो इन्होंने पाल रखा है। वास्तव में डेरी वहां बननी चाहिये जहां चारा हो, पानी हो, लेकिन ये शहरों में डेरी बनाते हैं। मैं जानना चाहता हूँ—क्या सरकार ने दूध का व्यवसाय करने वाले

लोगों का उत्पादन हा जो खर्चा है उसके बारे में कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया है ? क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह आदेश देगी कि खेतीहर मजदूरों, भूमिहीन लोगों को जो दूध का घन्धा करना चाहें, उनको दो-ढाई हजार रुपया कर्जा दिया जायगा, जिससे दूध की पैदावार भी बढ़े और इन लोगों को रोजगार भी मिल सके ?

श्री बी० पी० मोर्य : माननीय सदस्य ने जो अपनी भावना प्रकट की है, यदि वे इससे सम्बन्धित पांचवीं पंचवर्षीय योजना को पढ़ेंगे तो मेरा विश्वास है कि वे सन्तुष्ट हो जायेंगे।

श्री मधु लिमये : आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि लिखा कुछ जाता है, लेकिन उतना होता नहीं। चौथी योजना में क्या हुआ—आप जानते हैं।

श्री बी० पी० मोर्य : फास-बीड की जो गाये और भैंसें हैं उनका सीधा लाभ मार्जिनल फार्मर्स, स्माल फार्मर्स, खेतीहर मजदूरों को पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। जो गरीब तबका है, जो नीचे रह रहा है उनको देखते हुए है यह योजना बनाई गई है और इसका विवरण विस्तार से दिया गया है। जहां तक आरे-कालोनी का प्रश्न है, वह उनकी निगाह में सफेद हाथी होगा, लेकिन परसों में वही पर था और मैंने उनके जो कागजात देखे और मुद्रायना किया, उससे तो मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि वह एक आदर्श प्रोजेक्ट है।

Allocation for Development of Haldia Port

*164. SHRI A. K. M. ISHAQUE: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) Whether any allocation has been made for the development of Haldia Port during the Fifth Five Plan? If so, the amount thereof;